(लाख रुपये)

वर्ष	आबंटित/मंजूर अनुदान	दिनांक 30.6.1997 तक उपयोग किया गया अनुदान
1994-95	793.33	811.06
1995-96	858.00	737.44
1996-97	858.00	378.07

(ख) जलापूर्ति सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत तथा कुल साक्षरता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च की गई राशि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपये)

क्षेत्र	जारी की गई निधियां	व्यय	खर्च की गई राशि का प्रतिशत
सड़क	1086.37	1024.34	94.29
स्वास्थ्य	254.00	138.57	54.56
जलापूर्ति	467.18	243.97	52.22
विद्युत	300.00	229.50	76.34
कुल साक्षरता	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	2108.19	1636.38	77.62

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छानबीन समिति प्रत्येक तिमाही प्रगति की समीक्षा करती है तथा राज्य सरकार उस प्रगति रिपोर्ट की योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम संबंधी नीतिगत मामलों पर योजना आयोग में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है।

Revamping of Self-Employment Schemes

1055. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to thoroughly revamp the various self employment schemes, to make them more effective and acting as catalyst in tackling massive unemployment problem in the country;

(b) if so, the directives issued by Government in this regard; and

(c) by when a final decision to revamp them is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATANAMALA DEHARSHWAR SAVANOOR): (a) to (c) Government proposes to revamp and redesign the various Centrally Sponsored Schemes of self-employment to make them more effective. In this regard, a Committee was set up under the chairmanship of prof. S.R. Hasim, Member, Planning Commission to Review & Rationalise Centrally Sponsored Schemes of Poverty Alleviation and Employment Generation. The Committee has since submitted its reports, which is under the active consideration of the Government.